निस्केयर
NISCAIR

विज्ञान प्रगति

जनवरी 2016

प्रमुख सम्पादक
दीक्षा बिष्ट

सम्पादक
बालक राम

प्रोडक्शन अधिकारी
सुप्रिया गुप्ता
एस. पी. सिंह

कला अधिकारी
नीरू विजन

कम्पोज़िंग
मीरा देवी

वरिष्ठ बिक्री एवं वितरण अधिकारी
लोकेश कुमार चोपड़ा

आवरण
नीरू विजन

'भारत एक कृषि प्रधान देश है' और कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी बैकबोन है, लेकिन ऐसा लगने लगा है कि अन्धाधुंध प्रकृति का दोहन, कृषि भूमि पर अनियंत्रित फैलती विशालकाय बहुमंजिली इमारतें, जंगलों का कटान, प्रदूषण के कारण विषैला होता पर्यावरण आज अनेक गंभीर समस्याओं का दाता बन गया है।

हम आज कितना स्वास्थ्यवर्द्धक भोजन खा रहे हैं हमें खुद नहीं पता क्योंकि कभी फलों, सब्जियों को इंजेक्शन द्वारा आकार बढ़ाने की बात सामने आती है तो कभी रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से सब्जियों के हानिकारक होने की और कभी सब्जियों को तरोताजा दिखाने के लिये कृत्रिम रंगों में रंगने की। मटर और परवल जैसी सब्जियों को हरे रंग से रंगकर बेचना तो आम चलन हो गया है। जैसे ही आप सब्जियां धोयेंगे तो सारा पानी हरा हो जायेगा।

हर जगह स्वास्थ्य से खेल तो भला क्या चारा रह गया ताकि सबको स्वास्थ्यवर्धक और शुद्ध भोजन मिले। संभवतः इन्हीं कारणों ने हमें फिर पीछे अतीत में झांकने को विवश कर दिया है। आज से कई दशक पहले सब्जियों में हानिकारक रसायन पाये जाने की बात न के बराबर होती थी लेकिन विकास की अंधी दौड़ ने हर क्षेत्र को इतना हानिकारक बना दिया कि आज हम पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिये हर बात के हल के लिये पीछे अतीत में झांकने लगे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अतीत की बातों को अपना कर हमें वही सफलता मिल रही है जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं - ऐसा ही एक कारगर उपाय सामने आया है - ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती का, जिसमें अच्छी उपज के लिये सिर्फ और सिर्फ जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है और आज तो बाजार में जैविक खेती द्वारा उगाये गये उत्पाद बहुतायत में उपलब्ध हैं। ऐसे उत्पादों में स्पष्ट तौर पर लिखा होता है ऑर्गेनिकली ग्रोन या ऑर्गेनिक फूड।

यहां पर इस बात का जिक्र करना भी आवश्यक हो जाता है कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो वर्ष 2015 के अंत तक जैविक राज्य घोषित हो जायेगा। सिक्किम ने यह उपलब्धि सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन 2015 को अपना कर सफलता प्राप्त की है यानी वहां पर पूरे राज्य में सिर्फ जैविक खेती अनिवार्य है और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसमें अपील की गई है कि हिमालय प्रदेश के सभी देशवासी पर्यावरण की रक्षा और पूर्वजों की धरोहर की रक्षा के लिये जैविक खेती से उत्पन्न उत्पादों को अपनायें। इससे स्वस्थ जीवन के साथ-साथ आर्थिक लाभ तो होगा ही हम अपनी अमूल्य धरोहर धरती, जल स्रोतों और पारिस्थितिकी की रक्षा कर प्रकृति और पर्यावरण के बीच पूर्ण सामंजस्य भी बना पायेंगे। आशा है यदि सब राज्य इस प्रकार से पृथ्वी और उसके पर्यावरण की रक्षा के लिये ऐसे प्रण लेकर कार्य करें, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बंद कर दें तो निश्चित रूप से हम अपनी अमूल्य धरोहर को बचा पायेंगे अन्यथा बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा और हमें फिर लौटना होगा पारम्परिक खेती की ओर।

आपको यह अंक कैसा लगा प्रतीक्षा रहेगी।

विज्ञान प्रगति परिवार की ओर से नववर्ष की शुभकामनाओं सहित।

मूल्य

एक अंक	:	30.00 रुपये
एक वर्ष	:	300.00 रुपये
दो वर्ष	:	570.00 रुपये
तीन वर्ष	:	810.00 रुपये

विदेशी वार्षिक सदस्यता : 65$
शिकायत : 011-25841647
ई-मेल : lkc@niscair.res.in

सम्पादकीय : 011-25841769, 011-25846301, 04-07/370
प्रोडक्शन : 011-25847353, 25846301, 04-07/217, 337
विज्ञापन : 011-25843359
बिक्री : 011-25841647, 25846301, 04-07/286, 289
फैक्स : 011-25847062
ई-मेल : vp@niscair.res.in
वेब साइट : http://www.niscair.res.in

© राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान
लेखकों के कथनों ओर मतों के लिये सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान, डॉ. के. एस. कृष्णन् मार्ग, नई दिल्ली - 110 012 उत्तरदायी नहीं है।
पत्रिका से संबंधित सभी विवाद दिल्ली न्यायालय द्वारा ही निपटाये जायेंगे।